

प्रेषक,

एन0एस10नपलच्याल,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सोचामे,

जिलाधिकारी,

उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 14 मई, 2008

विषय:-मै0 विडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि0 को जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम कुदयोवाला में विडियोकॉन इण्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु 0.610 है0 भूमि कय करने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-531/सात-भू0अ0अ0/2007 दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 विडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि0 को विडियोकॉन इण्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम कुदयोवाला के खाटा संख्या- 00006 के खसरा नं0 371 मध्ये रकबा 0.160 है0, 372 रकबा 0.061 है0, 373 रकबा 0.3980 कुल रकबा 0.610 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि वन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकस्य उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों तक वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा, व 2 वर्ष के भीतर इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7- प्रस्तावित कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार खार्चवाही करते हुए भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अन्तर्गत GIDCR - 2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा एवं इकाई का निर्माण कार्य सीडा से ले-आऊट स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त शर्तों के क्रियान्वयन के अनुश्रवण का दायित्व उद्योग विभाग का होगा।

9- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग प्रस्तावित उद्योग के कार्यालय भवन, पार्किंग, जलपान, मनोरंजन कक्ष, प्रशिक्षण व हॉस्टल की सुविधाओं के विकास के लिये ही किया जायेगा।

10- कम्पनी द्वारा प्लास्टिक मोल्डेड कम्पोनेन्ट ए०सी० कन्डीशनर, वाशिंग मशीन, फ्रीजरेटर उत्पादक इकाई में उत्तराखण्ड के बैरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत का रोजगार दिया जायेगा।

11- इकाई में पूंजी निवेश एवं नियमानुसार योजना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग आदि से नियमानुसार स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाना अनिवार्य होगा।

12- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रश्नगत अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के सदर्भ में दी जा रही है।

13- प्रस्तावित भूमि भारत सरकार से अधिस्वीकृत नहीं है। अतः कम्पनी को प्रस्तावित उत्पादों के विनिर्माण की किसी भी गतिविधि किये जाने पर विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

14- किसी दशा में क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

15- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु संकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
- 2- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- निदेशक, उद्योग, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 7- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडी, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- 8- गैर विडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि०, भजीकृत कार्यालय आंदोलार कम्पाउण्ड, अदालत रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा, सं.  
(संगताप बलानी)  
अनुसचिव।